The Times of India- 26- October-2023

# NDSA team, T irrigation officials meet

**Hyderabad:** The National Dam Safety Authority (NDSA) investigating the subsidence of piers of Medigadda held a meeting with Telangana irrigation officials on Wednesday to collect technical data and other details.

The six-member NDSA team headed by its chairman Anil Jain had visited the barrage on Tuesday and inspected the piers from 19 to 22.

Sources said the team asked for technical details, tests done before executing the project and permissions pertaining to soil tests etc. TNN

The Hindu- 26- October-2023

# Cabinet panel clears funds for dam project in Uttarakhand

**The Hindu Bureau**
NEW DELH

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on Wednesday approved a Central support of ₹1,557.18 crore to Uttarakhand for the proposed Jamrani dam project in Naintal district.

The multipurpose project, estimated to cost around ₹2,584.10 crore, is scheduled to be completed by 2028. The CCEA has approved the inclusion of the project under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-Accelerated Irrigation Benefit Programme.

The project envisages the construction of a dam near Jamrani village across river Gola, a tributary of the Ram Ganga, in Nainital. The dam will feed the existing Gola barrage through its canals.

Deccan Herald- 26- October-2023

# Sinking reservoir pillars whip up political storm

A few pillars of the Medigadda (Lakshmi) reservoir at Mahadevpur in Telangana's Jayashankar Bhupalpally district that were found to be sinking two days ago have shaken the foundation of the BRS government's Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP), thickening the plot in the state's ongoing election drama, reports DHNS.

The Telangana government, which has built several reservoirs as part of its prestigious KLIP, is under attack by the Opposition Congress, which has alleged large-scale corruption compromising the quality of work at the Medigadda reservoir. Even as the ruling BRS government has suspected sabotage, the Congress has planned a 'visit' of irrigation experts to the KLIP to 'expose' the bad quality of work.

The BJP state president and Union Minister, G Kishan Reddy, on his part, had complained to the Centre to check the safety of the barrage. The Union Jal Shakthi minister has promptly deployed a six-member central team, led by Central Water Commission member Anil Jain.

Millennium Post- 26- October-2023

# Sikkim: NGT seeks report on Chungthang dam breach

*The tribunal transferred the matter to the Eastern Zone Bench, Kolkata for appropriate further proceedings*

**OUR CORRESPONDENT**

**NEW DELHI:** The National Green Tribunal has sought a report within six weeks from authorities concerned on the breach of Chungthang dam in Sikkim earlier this month.

A glacial lake outburst flood (GLOF) occurred in parts of Lhonak Lake, leading to a rapid rise in water levels with very high velocities downstream along the Teesta River Basin in the early hours of October 4.

The incident caused the breach of the Chungthang dam, a crucial component of the 1,200-megawatt (MW) Teesta Stage III Hydro Electric Project, the largest hydropower project in the state.

A bench of NGT Chairperson Justice Prakash Shrivastava and expert member A Senthil Vel said the tribunal had taken suo motu cognisance of the incident based on a media report.

The respondents comprise the state of Sikkim through its Chief Secretary, the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) through its Chairman and Managing Director and the Sikkim Urja Limited

The bench, in a recent order, noted that according to the report, there was a potential risk associated with some of the large-scale infrastructure projects, which require robust disaster preparedness.

"Let the report by the respondents be filed within six weeks before the Eastern Zone Bench, Kolkata," the tribunal said.

The respondents comprise the state of Sikkim through its Chief Secretary, the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) through its Chairman and Managing Director and the Sikkim Urja Limited.

The tribunal also transferred the matter to the Eastern Zone Bench, Kolkata for "appropriate further proceedings."

During the proceedings, the Advocate General appearing for the State of Sikkim sought time to place on record the cause of the incident, the remedial measures, the death toll and the state's scheme to provide compensation to the deceased.

The flash flood that hit the Himalayan state on October 4 has left at least 78 people dead in Sikkim and northern West Bengal and scores were still missing.

Haribhoomi- 26- October-2023

## निर्माण का रास्ता साफ: जमरानी बांध परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

# 1,50,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र होगा सिंचित, पेयजल समस्या होगी दूर

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। अब 150.60 मीटर ऊंचा बांध बनने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम पुष्कर धामी ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के अंतर्गत इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने पूर्व में स्वीकृति दी थी। वित्त मंत्रालय ने इसी वर्ष मार्च माह में आयोजित पीआईबी की बैठक में सहमति जताई थी। 1730.20 करोड़ की स्वीकृति परियोजना पर अब 90 फीसदी केंद्र जबकि शेष राशि राज्य सरकार की तरफ से खर्च किया जाना है। सीएम धामी इस परियोजना को लेकर लगातार प्रयासरत थे। पीएम मोदी से वे जमरानी बांध परियोजना को लेकर आग्रह कर चुके थे। जल शक्ति और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से लगातार संपर्क बनाकर रखा था।

जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर होना है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से होगा कार्य
- जल शक्ति मंत्रालय ने दी निवेश की स्वीकृति
- 90 फीसदी राशि का वहन केंद्र सरकार करेगी

### सीएम धामी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पीएम मोदी का जताया आभार

**351 हेक्टयर भूमि सिंचाई को हस्तांतरित**

परियोजना के दायरे में लगभग 351.55 हेक्टेयर वन भूमि भी आई है। यह भूमि पूर्व में ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सिंचाई विभाग को हस्तांतरित कर चुका है। बांध के बनने से काफी परिवार विस्थापित भी हो रहे हैं, जिनके विस्थापन के लिए प्राग फार्म की 300.5 एकड भूमि मई माह में राज्य सरकार मंजूरी दे चुकी है।

**चार दशक से थी प्रस्तावित**

नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाली जमरानी बांध परियोजना 1975 से प्रस्तावित थी। वित्तीय मंजूरी न मिलने से परियोजना का निर्माण अटका हुआ था। मुख्यमंत्री धामी की लगातार पहल के चलते अब जाकर परियोजना को स्वीकृति मिल पाई है।

**63 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन भी होगा**

इसके बनने से हल्द्वानी और आसपास के इलाके की पेयजल और सिंचाई की समस्या भी दूर होगी। काठगोदाम से 10 किमी के ऊपरी क्षेत्र में गौला नदी पर यह बांध बनना है, जिसके ऊंचाई लगभग 150.60 मीटर होगी। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई भी होनी है। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को पेजल उपलब्ध होगा।

## 7,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र व गोवा का दौरा करेंगे, जहां पर वे सबसे पहले महाराष्ट्र में शिरडी के प्रसिद्ध श्री साईंबाबा मंदिर में पूजा-अर्चना कर मंदिर के नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे निलवंडे बांध का "जल पूजन" भी करेंगे। इसी के लगभग 7,500 करोड़ की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे जिसमें स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल एवं गैस जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। पीएम मोदी शिरडी के परिसर में अत्याधुनिक क्यू कॉम्प्लेक्स का अनावरण करेंगे,जिसे भक्तों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें 10,000 से अधिक भक्तों की बैठने की क्षमता वाले कई प्रतीक्षा हॉल सुसज्जित हैं।

**नमो शेतकारी महासम्मान निधि**

पीएम नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का लाभ होगा।

**निलवंडे बांध**

पीएम निलवंडे बांध की आधारशिला रखेंगे जिसमें 85 किमी लंबे नहर नेटवर्क का पानी 182 गांव सीधे तौर पर लाभावित होंगे। 5,177 करोड़ की लागत है।

Jansatta- 26- October-2023

# जमरानी बांध परियोजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 25 अक्तूबर।

उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा।

उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किमी गौला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।

*बांध* के निर्माण से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा।
*मुख्यमंत्री* धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के तहत जमरानी बांध परियोजना के वित्त पोषण हेतु निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृतियों के बाद सार्वजनिक व्यय बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में आयोजित पीआइबी की बैठक में सहमति व्यक्त की गई।

केंद्र सरकार द्वारा 1730.20 करोड़ की स्वीकृति पीएमकेएसवाई में 90 फीसद ( केंद्रांश) 10 फीसद ( राज्यांश) के अंतर्गत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। शेष धनराशि का वहन संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ किए गए समझौता पत्र के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए प्राग फार्म की प्रस्तावित 300.5 एकड भूमि का प्रस्ताव 18 मई को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में पारित किया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि को शीघ्र ही सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने के लिए भी कार्यवाही गतिमान है। इसी क्रम में अब इस बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। जिसके बाद पेयजल सहित सिंचाई समस्याओं से लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलना तय है। 1975 से वित्त पोषण के अभाव में परियोजना का निर्माण शुरू नहीं हो सका था।